भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3249

जिसका उत्तर 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

07 चैत्र, 1947 (शक)

'विकसित भारत 2047' के लिए डिजिटल अवसंरचना और एआई-संचालित शासन के विस्तार की रूपरेखा

3249. श्रीमती संगीता यादव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'विकसित भारत 2047' विजन के तहत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और एआई-संचालित शासन के विस्तार के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो अगले दशक के लिए क्या प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके और डिजिटल दूरी को कम कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया।

भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए विकसित भारत 2047 विजन के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और एआई गवर्नेंस रोडमैप पर जोर दिया है। भारत सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजीलॉकर और एपीआई सेतु) के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डीपीआई को सफलतापूर्वक लागू किया है, सरकार का ध्यान प्राथमिकता वाले डोमेन में मूलभूत डीपीआई की सफलता को दोहराना है और इसलिए, क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, कृषि, सेवा वितरण, शहरी शासन आदि जैसे डोमेन में नए डीपीआई पर काम किया जा रहा है और उन्हें बढ़ाया जा रहा है।

भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले नवाचार के साथ सार्वजनिक वित्त पोषण को जोड़कर डिजिटल नवाचार को फिर से परिभाषित किया है। आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म फाउंडेशन के रूप में काम करते हैं, जबकि संस्थाएं उनके ऊपर एप्लिकेशन-विशिष्ट समाधान बनाती हैं। इस मॉडल को अब एआई

के साथ उन्नत किया जा रहा है, जो वित्तीय और शासन प्लेटफार्मों में इंटेलिजेंस सोल्युशनों को एकीकृत करता है। भारत के डीपीआई की वैश्विक अपील जी-20 शिखर सम्मेलन में स्पष्ट थी, जहां कई देशों ने समान ढांचे को अपनाने में रुचि व्यक्त की थी।

डीपीआई उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक डेटा सेट प्रदान करके एआई की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रेलवे, शासन और प्रशासन, पृथ्वी विज्ञान, ऊर्जा और बिजली, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, परिवहन और कानून और न्याय जैसे विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों और संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

भारत सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग का लोकतंत्रीकरण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हुए 'सभी के लिए एआई' की अवधारणा पर जोर देती है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई नवाचार और विकास को आगे बढाते हुए समाज के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करे। सरकार का दृष्टिकोण एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एआई का लाभ उठाने पर केंद्रित है। इस संबंध में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दे दी है, जो देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित एक मजबूत और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। यह मिशन सात मूलभूत स्तंभों; इंडियाएआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पर ध्यान केंद्रित करके भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के की दृष्टि से प्रेरित है ।

(ग): डिजिटल इंडिया पहलों तक मोबाइल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और इसके आधार पर इसके माध्यम से शहरी ग्रामीण विभाजन ख़त्म होता है। डिजिटल साक्षरता दर में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, भारत सरकार ने देशभर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)" नामक एक योजना लागू की। देशभर में 6.39 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। भारत के आम लोग डिजिटल इंडिया सेवाओं जैसे डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, ई-कोर्ट सुविधाओं का उपयोग कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन 'उमंग' प्रचालनरत है और व्यक्तियों के लिए 2000+ सेवाएं प्रदान करता है। सेवा वितरण के सहायक मोड का समर्थन करने के लिए, देश भर में 5.97 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कार्यात्मक हैं (ग्रामीण+शहरी), और ये केंद्र ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में लोगों को उनके इलाके के पास 800 से अधिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सेवा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद डीपीआई भाषिनी मंच,भारत की विविध आबादी के समक्ष आ रही संचार संबंधी बाधाओं का समाधान करता है। यह वंचित समुदायों के लिए डिजिटल उपकरणों तक अधिक पहुंच को बढ़ावा देता है।

(घ) और (ङ): एमईआईटीवाई 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकी सक्षम पहलों पर नीति आयोग के साथ-साथ अन्य मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। एमईआईटीवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में अन्य मंत्रालयों/विभागों की लगातार सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सरकार के पूरे प्रतिमान को बदलना है और सेवाओं को सहज, आसानी से सुलभ बनाना, जीवन और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है।

एमईआईटीवाई ने पीएम गति शक्ति (राष्ट्रीय मास्टर प्लान की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन) के विकास की सुविधा प्रदान की है और इसके लिए निरंतर रूप से परिचालन और रखरखाव सहायता प्रदान कर रहा है। पीएम गति शक्ति ने 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया है। एमईआईटीवाई की डिजिटल पहलें जैसे डिजिलाकर, उमंग, एपीआई सेतु, पोषण ट्रैकर, दीक्षा, आदि कई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही हैं।

******